है । तफसीलवार बातें मैंने आपको पत्र लिखा है, उस में बताई हैं । लेकिन फिर भी आप उठाने नहीं देते हैं । 197 जो नियम है उस नियम में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक हित के मामले को और अविलम्बनीय महत्व के किसी भी प्रश्न को आपकी खाली अनुमति ले कर उठाया जा सकता है । अनुमति लेने का क्या यह मतलब है कि आपको वीटो का अधिकार है ? हर महत्वपूर्ण सवाल पर आप वीटो इस्तेमाल करते जाएं ? पहले अनुमति लेने का केवल यह मतलब है कि यकायक कोई ऐसा मामला न आए जिसकी पहले से आपको सूचना न दी गई हो । पहले प्रश्न आया था । उसका जवाब हम ने ग़ौर से पढ़ा । है और ग़ौर से पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया जाना चाहिये । इसलिए कृपा करके आप इसको स्वीकार करें । इसको कल रखें, परसों रखें, यह आप पर निर्भर करता है । इससे एक लाख मजदूर तथा उनके कुटुम्बियों का सम्बन्ध है । यह कोई मामूली सवाल नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अख्त्यार है कि मैं अपना फैसला दू ?

श्री मधु लिमये : वीटो का अधिकार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वीटो का मतलब तो यह है कि फैसला किसने देना है । असल में तो देखना यह है कि किस ने फैसला देना है और वह माना जाएगा या नहीं माना जाएगा ।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : माना जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या हर एक मैम्बर फैसला करेगा कि आया जो मैं फैसला दूं वह ठीक है या नहीं ?

श्री मधु लिमये : माने बतायें ।

अध्यक्ष महोदय : माने और कुछ नहीं बता सकता हूं । जो फैसला मैंने किया है उसी पर मैं कायम हूं । और मैं कोई वजह नहीं देखता हूं कि उसको मैं बदलूं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, एक और महत्व का सवाल . . .

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से कोई सवाल नहीं उठाने दे सकता हूं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : बहुत महत्व का सवाल है । चीन और पाकिस्तान जो भूमि दबाये हुए हैं, उसको वापिस नहीं लेना . . .

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से कैसे उठा सकते हैं ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : प्रधान मंत्री बैठे हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं उठा सकते हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : किस तरह से उठा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये ।

12.14 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*contd.*

(ii) Postponement of Afro-Asian Conference in Algiers—*Contd.*

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Considering that China, after the ignominious failure of its diabolical conspiracy in Indonesia, had strenously advocated postponement of the Algiers Conference fearing loss of face and loss of support in the Afro-Asian world whereas India had opposed such postponement all along, does the postponement now *sine die*, that is the virtual abandonment of the conference, signify a diplomatic

[Shri Hari Vishnu Kamath]

victory for China and a diplomatic reverse for India, and is the blow, to which the statement refers, to Afro-Asian solidarity so severe that an Afro-Asian summit conference is virtually **or well nigh impossible in the near** future?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): If I have understood the question correctly, there are two points upon which my reply is required. One was whether it was a diplomatic victory for China and a reverse for India. I have attempted to deal with this to a certain extent, though not in this very language. In the balance, I feel that this could not be termed as a diplomatic victory for China although they were for postponing and they had approached various governments. The fact remains that when the Algerian government, the host, asked and sounded the various countries, a large majority of them were in favour of holding the conference. Although they had gone to Algiers, they decided that it should be postponed mainly for the reason that a large majority of the heads of States and governments would not be able to attend the conference. The second point was....

Shri Hari Vishnu Kamath: Severe blow to the solidarity.

Shri Swaran Singh: I have myself said that this is to a certain extent correct—not so much the postponement—because this is a symptom, of the unfortunate absence of solidarity at the moment and this is really a confirmation of the fissures which unfortunately had been developing for sometime in the concept of Afro-Asian solidarity.

Shri Hari Vishnu Kamath: My question was whether the Government think that the Afro-Asian summit conference is virtually impossible in the near future.

Shri Swaran Singh: I have answered that in the main reply itself.

श्री मधु लिमये : सरकार ने अफ्रो-एशियाई सम्मेलन के सामने जो प्रश्न उठाये थे और यह सम्मेलन बुलाने के बारे में सरकार की जो नीति थी क्या उस नीति के सम्बन्ध में हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल है, सीलोन है, क्या यह सही है, कि इन्होंने हिन्दुस्तान का साथ देने के बजाय चीन का साथ दिया? अगर यह बात बात सही है तो क्या सरकार अपनी विदेश नीति के बारे में पुनर्विचार करेगी जिससे पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो जायें ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारी हमेशा कोशिश और इच्छा रही है कि हमारे जो पड़ोसी देश है उन से हमारी मित्रता बढ़े और मैं कह सकता हूं कि मित्रता मजबूत है । यह कहना कि इस मामले में उन्होंने चीन का साथ दिया सही नहीं होगा । चीन चाहता था कि कोई देश वहां न जाये । नेपाल और सीलोन दोनों देश वहां गए । बर्मा भी मेरे ख्याल में गया । उनका सवाल सिर्फ नेपाल और सीलोन के मुताल्लिक था ।

श्री मधु लिमये : बर्मा भी तो पड़ोसी है ।

श्री स्वर्ण सिंह : बर्मा के साथ मैं समझता हूं कि हमारे बहुत मित्रता के सम्बन्ध हैं । उन्होंने नीति में तबदीली करने का सवाल भी उठाया है । यह सवाल इसलिए पैदा नहीं होता क्योंकि हम पहले ही इस बात को को समझे हुए हैं कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध दोस्ती के, मित्रता के हों और हमारे आपसी सम्बन्ध मजबूत हों ।

श्री मधु लिमये : प्रश्न क्या था । आप स्वयं सोच लीजिये, अध्यक्ष महोदय मैंने पूछा था कि यह सम्मेलन बुलाने के बारे में और स्थगित करने के बारे मे हिन्दुस्तान की एक भूमिका थी और चीन की दूसरी थी । हिन्दुस्तान के द्वारा इस सम्मेलन के सामने

कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए गए । उन प्रश्नों के बारे में तथा सम्मेलन स्थगित करने के बारे में मुझे सीधा जवाब चाहिये । नेपाल, सीलोन, बर्मा आदि पड़ोस वाले जो देश हैं उन्होंने हिन्दुस्तान का साथ दिया या चीन का साथ दिया ? उसका जवाब मंत्री महोदय दें । मित्रता बढ़ाने के बारे में क्या सरकार कर रही है, उस के सम्बन्ध में निष्कर्ष सदन निकाल सकता है । मेरे प्रश्न का जवाब नहीं

अध्यक्ष महोदय : जवाब दिया तो है कि . . .

श्री मधु लिमये : नहीं दिया है । सम्मेलन स्थगित करने के बारे में हिन्दुस्तान का साथ उन्होंने दिया है या चीन का साथ दिया है ? दूसरा हिस्सा यह था कि हम ने जो प्रश्न वहां पर उठाये थे जैसे सोवियत संघ को वहां पर शामिल करो आदि उन के बारे में भी पड़ोस वाले देशों की क्या नीति रही है ? उनकी चीन की भूमिका के बारे में क्या नीति रही है और हमारे बारे में क्या रही है ? यह सवाल था जिसका जवाब नहीं आया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : चीन तो वहां मौजूद नहीं था, इसलिए चीन ने तो कोई सवाल वहां नहीं उठाया । उनकी इच्छा जरूर थी. . . (इंटरप्शंज)

अध्यक्ष महोदय : किसी वक्त भी बन्द होंगे या नहीं ? जवाब आपने पूछा है और वह अब जवाब दे रहे हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : जैसे मैंने कहा है कि यह ख्वाहिश थी कि कोई देश वहां न जाए । उस ख्वाहिश के बावजूद सीलोन और नेपाल जिन के मुताल्लिक माननीय सदस्य पूछते हैं वे दोनों वहां गए ।

दूसरा सवाल यह पूछा गया कि जो सवाल हम ने उठाये थे उन में उन्होंने हमारे प्रपोजल्स की ताईद की या नहीं । सिर्फ दो ही बातें कांफरेंस में उठाई गई थीं । एक सवाल था कि सोवियट यूनियन, मलयेशिया, और सिंगापुर, जिन के मुताल्लिक हिन्दुस्तान ने तजवीज की थी, इन तीनों देशों को ऐफ्रो एशिया कांफरेंस में बुलाया जाये, दूसरा जो सब्स्टैन्टिव सवाल उठा था था वह पोस्टपोनमेन्ट के मुताल्लिक था । सोवियट यूनियन के मुताल्लिक किसी ने भी मुखालिफत नहीं की । कोई बीस या बाईस देश वाले थे । उन्होंने इसकी हिमायत की । इसी तरह से सिंगापुर और मलयेशिया के मुताल्लिक जिन्होंने हिस्सा लिया उन में से सिवा इंडोनीशिया के जिस ने कुछ थोड़ा सा मलयेशिया के मुताल्लिक कहा, बाकी सभी देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात की ताईद की, इस की मुखालिफत नहीं की । इस से मैं नहीं चाहता कि कोई नतीजा निकाला जाये कि हमारे पड़ोसी देशों ने किसी तरह से भी हमारी मुखालिफत की ।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : क्या पिछले अनुभवों के बाद भारत सरकार इस सत्य को समझने लगी है कि ऐफ्रो एशिया एक नहीं बल्कि चार हैं : पूंजीवादी ऐफ्रो एशिया कम्यूनिस्ट ऐफ्रो एशिया, नकली समाजवादी ऐफ्रो एशिया और समाजवादी ऐफ्रो एशिया ।

श्री स्वर्ण सिंह : उन्होंने जो कहा वह ठीक हो सकता है । कइयों में आइडियालोजिकल फर्क भी है । हर एक देश में मुख्तलिफ किस्म के ख्याल हैं एकानमी के मुताल्लिक और पॉलिटिकल ।

Shri Narasimha Reddy (Rajampet): I would like to know whether after this recent, sudden and last-minute volte-face of the UAR and kindred Arab nations, would the Government give up its exclusive reliance on the Arab nations and instead cultivate friendly relations with more reliable nations like Israel and Formosa?

Shri Swaran Singh: I do not accept the suggestion made by the hon. Mem-

[Shri Swaran Singh.]

ber in which he used the word 'unreliable' in relation to the Arab group of countries.

Shri Narasimha Reddy: I did not say 'unreliable'. I had asked him to cultivate more reliable relations. (*Interruption*).

Shri Kapur Singh: Diplomatic relations with Israel.

Shri Swaran Singh: It should be our endeavour to have friendly relations with all countries; that has been our endeavour. (*Interruption*).

An hon. Member: Israel.

Shri Swaran Singh: But there is no question of not recognising Israel; we do recognise Israel. There is no question on that issue.

Shri R. S. Pandey: May I know whether it is a fact that China had stipulated three conditions for agreeing to attend the conference and, if so, what are those conditions and whether any condition was accepted by the Standing Committee of the Foreign Ministers' Conference?

Shri Swaran Singh: The Chinese had laid down certain impossible conditions and they were publicised on the eve of the conference. They had said that they would attend if the Soviet Union is not invited, and some sort of advance guarantee is given to that effect. They also said that on certain issues specific resolutions of the type that they wanted should be adopted. In a conference any party, before attending, cannot demand as to what the conference should do. There were strong reactions against that suggestion, and none of those things really were even considered by the conference because they were conditions which were impossible conditions.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): When the first Afro-Asian conference was held at Bandung, our country played a very major role there. In fact, it was one of the sponsors of the Bandung Conference. May I know what has happened. . . .

Shri Kapur Singh (Ludhiana): "Very major role" is wrong English.

Shri D. C. Sharma: I think it is very right English, but the hon. Member, I think, knows nothing about English. His language is Punjabi and he is for Punjabi Suba, and therefore, he does not know anything. Sir, I was submitting very respectfully that the first Afro-Asion conference was held at Bandung about 10 years ago and our country played a major role in the convening of that conference and also in the deliberations of that conference. May I know what has happened during these ten years that we have come to occupy a place in the Afro-Asian world which is so inferior and also our voice has become so feeble that we cannot carry other people with us?

Shri Swaran Singh: Our country, along with other important countries of Afro-Asia did play some role at the time of the Bandung Conference ten years ago. At that time, there was a certain political relationship between the countries which participated in that conference. If you compare that with their relationship today, the answer to the Professor's question is there. So, after all, the Afro-Asian world itself or the solidarity or the inter-relationship of various countries is something which is not entirely within our control. That relationship reflects both the atmosphere and the possible role that any country including India can play. About the second suggestion of the hon. member, I do not accept that our voice is feeble. Our voice is there and even in this conference of foreign ministers where 45 countries were there, our country made the main proposal which was the only substantive proposal, because postponement cannot be regarded as a substantive proposal, and there was a consensus in favour of the Indian proposal.

Shri D. C. Sharma: We made a substantive proposal and nobody listened to that! What is this logic?

Shri Hem Barua (Gauhati): In spite of the adroit advocacy by our delegation at Algiers, China, as claimed by Peking, has scored a diplomatic victory at Algiers by manoeuvring to get the Afro-Asian conference postponed. In that context, may I know if our Government have conducted any probe into the reasons, both psychological and political, why some of the African nations, most of whom are opposed to communism, supported China and not India at Algiers?

Shri Swaran Singh: It is not correct that most of the African countries, about which the hon. member is asking the question, supported the Chinese stand.

Shri Hem Barua: I said, some.

Shri Swaran Singh: In fact, one of the reasons which could be regarded as a possible motive by China to ask for postponement was that China did not actually have the support which at one time China thought it had in the African world. That is considered to be an important reason which prompted China to make a move for postponement, which was a complete reversal of their original anxiety to hold the conference. So, the premise which the hon. member is projecting is not quite correct. As for China treating this as a victory, well, in any circumstance for their own consumption and for satisfying their own pride or their people, they can always give a particular projection of what happened in a most favourable form, so that they may always convert even their set-backs into advances or gains!

Shri Hem Barua: The minister said that China projected it for the consumption of their own people. Not that; China has projected that image for the consumption of the people all over the world.

1711 (Ai) LSD—4.

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : जैसा मंत्री महोदय ने बतलाया है, भारतवर्ष ने बहुत काफी कोशिश की कि यह सम्मेलन हो, लेकिन परिस्थितियों के कारण यह सम्मेलन स्थगित हो गया । यह कई बार और भी स्थगित हो चुका है । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में क्या यह सम्मेलन पुन: होने वाला है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : उसके मुताल्लिक मैंने अपना बयान कल सभा पटल पर रखा था । उस में इसका जिक्र है ।

श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़) : भारत चीन संघर्ष के समय यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गयी थी कि अफ्रीका और एशिया के कितने देश हमारे साथ हैं । इस स्थिति का पता लग जाने के बाद कौन से ऐसे कारण थे कि जिन के आधार पर सरकार इतनी उतावली थी कि यह अल्जीरिया की कानफरेंस हो जाए ? किस कारण उस ने इस के लिए बयान दिए ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमें यह बात सामने रखनी चाहिए । अल्जीरिया की तरफ से जब दूसरे देशों से इस के मुताल्लिक पूछा गया कि वह कानफरेंस में आना चाहते हैं या नहीं तो उस में करीब 49 देश आए, यानी बड़ी भारी गिनती में देश आए । वह चाहते थे कि कानफरेंस हो । जब सब लोगों की यह इच्छा थी तो हमारे लिए भी यह स्वाभाविक था कि हम भी चाहते । और हम ने इस बात को भी साफ कर दिया था कि यदि बहुमत इस बात के हक में ही हो कि कानफरेंस न हो तो उनकी मर्जी के मुताबिक हम भी चलेंगे । हर बात में उनकी हार समझना उचित नहीं है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इस परिषद् ने एशिया के देशों की प्रगति के लिए कोई भी काम नहीं किया है, इसके प्लेटफार्म का केवल प्रोपेगेन्डे के लिए उपयोग किया जाता है ।

[श्री हुकम चन्द्र कछवाय]

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस परिषद को पुन: बुलाने के लिए यह सरकार कुछ करने जा रही है ?

Shri Swaran Singh: I am sorry, Sir, I have not followed the first part of the question.

Mr. Speaker: He wants to know whether the Government is going to take any action so that this Conference may be reconvened in the near future. Is that the question?

Shri Nath Pai: No. His question was this. He said that no good has come for any Asian country from this Conference. In spite of this experience and the fact that this platform is utilised for propaganda against India, he asked, will the Government persist in its effort to convene the Conference; if so, why?

Shri Swaran Singh: We have made the position clear—if that is the question really that as been put—

Shri Nath Pai: That is exactly the question that was put.

Shri Swaran Singh: We have made the position clear that if and when there is any proposal for re-convening the Conference we will consider as to what is the situation that prevails at that time and in the light of the situation prevailing we will react to the possible proposal, which I do not anticipate in he near future of any proposal being put forward, for convening the Afro-Asian Conference.

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): I would only like to know when the Government of India knew that the host country, Algeria, was also in favour of postponement of this Conference? If they had known it before our delegation left India, was it necessary for them to send the entire delegation; could they not have managed with only sending the Secretary General for the Conference thus saving a good deal of foreign exchange?

Shri Swaran Singh: It was only when the discussions proceeded there that it appeared that the Algerian Government also were not very anxious to convene the Conference. Not only right up to the date of convening the Conference but even in the initial stages of the Conference the Algerian Government was very anxious and keen that the Conference should be held. In fact, the Foreign Minister of Algeria met me only, I think, two or three days before the Foreign Ministers' Conference in New York, and he himself gave me the impression of showing very great keenness and desire for convening this Conference.

Some hon. Members *rose—*

Mr. Speaker: Let us proceed now to the next item.

Shri Hem Barua: I think the Prime Minister wants to say something on that.

—

12·33 hrs.

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT (*Query*)

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने वायदा किया कि प्रधान मंत्री जी से बातचीत करेंगे.

अध्यक्ष महोदय : अभी आपको इत्तिला दे देता हूं। मैंने आज सुबह आपके कागज देखे है । जो कुछ हुआ है उसकी आपको इत्तिला मिल जाएगी ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह इत्तिला कितनी देर बाद मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय : एक नोटिस तो आपका जहां तक मुझे याद है, हाजी पीर है । हाजी पीर पर मलहिदा से डिसकशन के लिए मैं